

द बगि पक्किचर/देश-देशांतर : भारत की वकिस दर: वशिव बैंक की रपिर्ट और उपाय

संदर्भ और पृष्ठभूमि

वशिव बैंक ने हाल ही में ग्लोबल इकॉनमिक प्रॉस्पेक्ट रपिर्ट 2018 जारी की, जसिमें वमिद्रीकरण और जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को लगे शुरुआती झटकों के बावजूद 2017 में वकिस दर 6.7 प्रतशित रहने का अनुमान जताया गया है। यह वशिव बैंक द्वारा पहले लगाए गए अनुमान 7 प्रतशित से कुछ कम है।

रपिर्ट के प्रमुख बदि

- वशिव बैंक ने 2018 के लिये भारत की वकिस दर 7.3 प्रतशित और अगले दो सालों के लिये 7.5 प्रतशित रहने का अनुमान जताया है।
- चीन से भारत की तुलना करते हुए चीन की अर्थव्यवस्था को धीमा बताया है। 2017 में चीन की अर्थव्यवस्था 6.8 प्रतशित की रफ्तार से बढ़ी यानी भारत की तुलना में केवल 0.1 प्रतशित अधिक।
- 2018 में चीन के लिये अनुमान 6.4 प्रतशित वकिस दर और अगले दो सालों के लिये यह अनुमान घटाकर क्रमशः 6.3 और 6.2 प्रतशित कर दिया गया है।
- रपिर्ट में कहा गया है कि अगले दशक में भारत की वकिस दर औसतन 7 प्रतशित बनी रहेगी।
- रपिर्ट में भारत को अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करने के लिये नविश की संभावनाओं को बढ़ाने वाले कदम उठाने के लिये कहा गया है।
- श्रम सुधार, शकिसा, स्वास्थ्य में सुधार और नविश के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर करने से भारत की संभावनाएँ और बेहतर होने की बात भी रपिर्ट में कही गई है।
- रपिर्ट में भारत के जनसांख्यिकी लाभांश (Demographic Dividend) की तारीफ करते हुए कहा गया है कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा प्रायः देखने को नहीं मलित्ता।
- रपिर्ट में अन्य वकिसशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में महिला श्रम का अनुपात कम होने पर चत्ता जताते हुए कहा गया है कि महिला श्रम की हसिसेदारी बढ़ाकर वकिस की रफ्तार काफी तेज़ की जा सकती है।
- रपिर्ट में भारत के सामने बेरोज़गारी घटाने जैसी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन चुनौतियों से नपिटने में सफल रहने पर भारत अपनी क्षमता का अधिक इस्तेमाल कर पाएगा।
- वशिव बैंक के अनुसार देश में हो रहे व्यापक सुधार उपायों के साथ भारत में वशिव की अन्य कई वकिसशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वकिस की कहीं अधिक क्षमता है।

वशिव बैंक की कारोबार सुगमता रपिर्ट

पछिले वर्ष नवंबर में वशिव बैंक द्वारा जारी कारोबार सुगमता रपिर्ट अर्थात् ईज़ ऑफ डूइंग बज़िनेस रैंकगि में भारत 2016 के 130वें स्थान से 30 स्थानों की छलांग लगाते हुए 100वें स्थान पर पहुँच गया। जल्द कारोबार आरंभ करने के मामले में 156वें, उद्योगों को बजिली कनेक्शन देने के मामले में 129वें, दवालिया मामलों के नपिटान के मामले में 103वें स्थान पर है। इन सभी में भारत की रैंकगि में पहले के मुकाबले सुधार हुआ है। रपिर्ट के अनुसार इनके अलावा, जहाँ एक ओर कारोबार के लिये ऋण लेना भी आसान हुआ है, वहीं अल्पसंख्यक शेरधारकों की हतियों की रक्खा के लिये अहम् कदम उठाए गए हैं, साथ में कर-अदायगी को आसान बनाने की दशिया में भी सुधारों को बल मलिया है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

वकिस दर बनाए रखने के लिये करने होंगे ये उपाय

सीएसओ ने हाल ही में वकिस दर को लेकर जो पहला प्राथमिक अनुमान जारी कया है, उसके अनुसार देश की अर्थव्यवस्था पछिले चार वर्षों में सबसे सुस्त दौर से गुज़र रही है। ऐसे में वकिस दर को बनाए रखना सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, जसिके लिये उसे कुछ उपाय तुरंत करने होंगे।

कृषि क्षेत्र पर देना होगा ध्यान

वकिस दर बढ़ाने के लिये कृषि को प्राथमिकता दिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब फसल अच्छी होती है तो सब कुछ ठीक रहता है तथा मौद्रिक नीति भी कारगर साबत्ति होती है। लेकिन जब फसल अच्छी नहीं होती तो महँगाई बढ़ने, वकिस दर कम होने जैसी चत्ताएँ सरि उठाने लगती हैं। यद्यपि वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बहुत अधिक नहीं है, फरि भी कृषि उत्पादन में गरिावट वकिस दर को नशिकत्ति ही प्रभावत्ति करती है।

कृषि क्षेत्र की वर्तमान दशा को समझने के लिये यह जान लेना पर्याप्त होगा कि स्वतंत्रता के समय देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत था, जो अब घटकर 14 प्रतिशत रह गया है। सर्वाधिक उत्पादकता वाले इस क्षेत्र पर देश की लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है। घटी हुई विकास दर न केवल कृषि पर निर्भर देश के 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महंगाई से परेशान हो जाता है। चूंकि देश की बहुत बड़ी आबादी रोजगार के लिये खेती-किसानी से जुड़ी हुई है, इसलिये कृषि में किसी भी प्रकार की गतिरोध रोजगार संकट को भी बढ़ा देती है।

रोजगार और कुशल श्रम का सृजन

भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक बड़ी चुनौतियों में से एक है रोजगार सृजन की चुनौती। इस समस्या के समाधान के लिये एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

- हमारे देश में लगभग 13-15 लाख युवा प्रतिवर्ष कार्यशील जनसंख्या में तबदील हो जाते हैं, जो रोजगार के उपयुक्त अवसरों की तलाश में रहते हैं।
- देश की लगभग आधी आबादी कृषि क्षेत्र में लगी है और वहाँ और अधिक लोगों को रोजगार दे पाना संभव नहीं है। अतः समय की मांग यही है कि गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उपाय किये जाएँ।
- यदि देश में गरमिपूर्ण रोजगारों का सृजन करना है तो सर्वप्रथम श्रम कानूनों के आधिक्य को कम करना होगा।
- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बहुत अधिक श्रम कानून हैं, जो प्रायः औद्योगिक विकास में बाधक बनते हैं।
- कठोर श्रम कानूनों के कारण औद्योगिक प्रगति नहीं हो पाती, जो आगे चलकर रोजगारहीनता का एक बड़ा कारण बन जाती है।
- श्रम सुधारों को कारोबार से जोड़कर ही मानव संसाधन को उत्पादक संपत्ति बनाना संभव हो पाएगा।

इसके अलावा रोजगार सृजन के लिये अनुकूल माहौल बनाना भी बेहद आवश्यक है। जहाँ एक तरफ छोटे एवं मध्यम उद्यमों से बोझ घटाने की ज़रूरत है, वहीं ऐसे सुधारों को कामगारों के लाभ से भी जोड़ना होगा।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

अंतरराष्ट्रीय मानकों पर तुलना करने से पता चलता है कि हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अनेकानेक खामियाँ हैं। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र के नियमों एवं प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता है, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में संबन्धित नियमों एवं प्रावधानों को। भारत में विश्वविद्यालयों का प्रबंधन, शैक्षिक कार्यक्रम तथा डिग्री देने की प्रक्रिया बदलते वक़्त की मांग के अनुरूप नहीं है।

- देश में उस ज्ञान-कौशल की पहचान करने की ज़रूरत है, जो रोजगार सृजित कर सके और युवाओं के लिये आगे का रास्ता तय कर सके।
- इसके लिये विभिन्न संगठनों और संस्थानों को विश्वविद्यालयों में शोध-आधारित गतिविधियों को चलाने के लिये आगे आना चाहिये।
- भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों एवं निकायों को इस बात की स्वायत्तता मिलनी चाहिये कि वे स्वयं की ज़रूरतों के हिसाब से 'अध्यापकों' का चुनाव कर सकें।
- वैसे लोग जो औद्योगिक विकास की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को समझते हों, उन्हें विश्वविद्यालयों से जोड़ना होगा और इसके लिये विश्वविद्यालयों की कार्य-संस्कृति में बदलाव करना होगा।
- देश की आर्थिक स्थिति बदल रही है, ऐसे में शिक्षा क्षेत्र में डिजिटलीकरण की भूमिका बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

बढ़ानी होगी क्रेडिट ग्रोथ

एनपीए के चलते सरकारी बैंक कर्ज़ देने में बेहद सावधानी बरत रहे हैं और कर्ज़ देने की रफ़्तार कम होने के कारण बैंकों के पास जमा राशालिगातार बढ़ रही है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है।

- एनपीए के उच्च स्तर के अलावा कमज़ोर कॉरपोरेट मांग के चलते देश में क्रेडिट ग्रोथ 60 साल के नचिले स्तर पर आ गई है।
- वित्त वर्ष 2016-17 में बैंकों की ओर से कर्ज़ देने की रफ़्तार गरिकर केवल पाँच प्रतिशत रह गई। इससे पहले क्रेडिट ग्रोथ की न्यूनतम दर 1953-54 में रिकॉर्ड की गई थी, जो तब केवल 1.7 प्रतिशत थी।
- कर्ज़ देने के ये आँकड़े इसलिये भी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान देश की विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रही और ब्याज दरें भी अपेक्षाकृत कम रहीं।
- बैंकों का एनपीए 14 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गया है, जो बैंकिंग सिस्टम का लगभग 15 प्रतिशत है।
- बीते वित्त वर्ष में बैंकों में जमा नकदी 11.75 प्रतिशत बढ़कर 108 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई, जो 1 अप्रैल, 2016 को 96.68 लाख करोड़ रुपए थी।

इसकी एक बड़ी वज़ह यह भी है कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ से कंपनियाँ कार्यशील पूंजी के लिये धन जुटा रही हैं।

अर्थव्यवस्था में नज़ी नविश लाने की चुनौती

पछिले वर्ष सितंबर में भारतीय उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन एसोचैम द्वारा आयोजित 10वें अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण शिखर सम्मेलन में भारतीय रज़िर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने भारत की गरिती अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिये केंद्र सरकार को महत्त्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा था कि यदि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है तो नज़ी नविश को बढ़ावा देना होगा। अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करने के लिये सरकार को प्रोत्साहन पैकेज के साथ-साथ नज़ी नविश को बढ़ावा देने की खातिर पूंजी व्यय बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिये। सरकार जिस भी तरीके से नज़ी नविश को बढ़ावा दे सकती है, वही उपयुक्त तरीका होगा।

गंभीर बात यह है कि निजी निवेश गिरा है और वास्तविकता यह है कि पूंजी पर सार्वजनिक व्यय में बहुत कम वृद्धि हुई है। ऐसे में सबसे ज़रूरी मुद्दा उन समस्याओं के समाधान का है, जो निजी निवेश को बाधित कर रही हैं। कई परियोजनाएँ जो रुकी हुई हैं, उन पर काम शुरू होना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ बैंकिंग प्रणाली के पुनर्पूँजीकरण पर पर्याप्त ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि निवेश के लिये अतिरिक्त कर्ज़ उपलब्ध कराया जा सके।

वनिर्माण क्षेत्र में सुधार

नीति आयोग का मानना है कि देश को वर्तमान विकास दर से कहीं उच्च विकास दर से बढ़ना है तो यह वनिर्माण के बिना संभव नहीं होगा, जो कि विकास का प्रमुख वाहक है। लंबे समय तक उच्च विकास दर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, कम-से-कम तीन दशकों या उससे अधिक समय तक विकास दर को बनाए रखना वनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन दिये बिना संभव नहीं हो सकता। वनिर्माण क्षेत्र में अधिकांश उद्योग प्रत्येक प्रत्यक्ष रोज़गार के साथ तीन अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराता है, इसलिये और अधिक रोज़गार उत्पन्न करने के लिये स्थानीय वनिर्माण ढांचे में सुधार के लिये मलिकर काम करने की ज़रूरत है।

अंकटाड की रिपोर्ट में भी 6.7 प्रतिशत थी विकास दर

पछिले वर्ष सितंबर में जारी हुई अंकटाड (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) की वार्षिक व्यापार और विकास रिपोर्ट में भी 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई थी, जो वर्ष 2016 के 7 प्रतिशत से कम है। इस रिपोर्ट में इसका कारण वमिद्रीकरण तथा जीएसटी को माना गया था।

- तब भारत की विकास दर को लेकर अर्थशास्त्रियों का कहना था कि कमज़ोर औद्योगिक उत्पादन और वनिर्माण में मंदी के चलते 2017-18 में देश की विकास दर में कमी आएगी।
- अंकटाड ने अपनी इस रिपोर्ट में भारत और चीन की धीमी विकास दर के संबंध में कहा था कि यदि भारत और चीन की वर्तमान वृद्धि दर स्थिर रहती है, तो भविष्य में इन दोनों देशों के वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास स्तंभ बनने की संभावना बहुत कम है।
- अल्प क्रेडिट उपलब्धता के कारण प्रभावित होते निवेश और उपभोग के संबंध में अंकटाड द्वारा रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास काफी हद तक बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर निर्भर करता है, लेकिन देश का बैंकिंग क्षेत्र पहले ही भारी-भरकम एनपीए के बोझ तले दबा है।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कर्ज़ पर अधिक निर्भरता होने के कारण भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में न तो तेज़ी आ पा रही है और न ही इनकी विकास दर स्थिर हो पा रही है।
- इसके अलावा पछिले वर्ष की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अपने 'वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक' में 2017 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटकर 6.6 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान लगाया था।

इसके अलावा हाल ही में देश में विकास दर का अनुमान लगाने वाली सरकारी एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (Central Statistical Office-CSO) ने इस वित्त वर्ष में देश की विकास दर पछिले वर्ष की तुलना में कम रहने का अनुमान जताया है। इसके अनुसार यह विकास दर चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 6.5 प्रतिशत पर चार साल के नचिले स्तर पर रहेगी। सीएसओ ने पहले इसके 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

(टीम वृषट्टा इनपुट)

निष्कर्ष: हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ 2 प्रतिशत से अधिक आर्थिक विकास दर को अच्छा माना जाता है, लेकिन यह केवल पश्चिमी विकसित देशों पर ही लागू होता है। भारत को उनके समकक्ष आने के लिये लंबे समय तक अपनी विकास दर को 7 प्रतिशत से अधिक बनाए रखना होगा। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बेशक भारत के उजले विकास का खाका खींचा है, लेकिन इसे पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वर्तमान में देश की विकास दर का निरंतर कम होते जाना वाकई चिंताजनक है। हालाँकि विकास दर में यह कमी वैश्विक मंदी तथा घरेलू स्तर पर वमिद्रीकरण और जीएसटी लागू होने तथा कुछ अन्य कारणों से आई है, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिये भागीरथ प्रयास करने होंगे। विकास दर में कमी के साथ निर्यात के समकक्ष भी कई चुनौतियाँ सामने आई हैं। इनके निराकरण के लिये ऐसी ठोस नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है जो घरेलू स्तर पर तो अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करें ही, साथ ही वैश्विक आर्थिक हलचलों से भी सुरक्षा दिला सकें। विकास दर को सुधारने के लिये सरकार को नीतिगत और निवेश के स्तर पर कई कार्य करने होंगे, जिनमें सुधार की दशा में आगे बढ़ने, अधिक पारदर्शी एवं अधिक वास्तविक राजकोषीय अनुशासन बनाये रखना प्रमुख है।